Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2023 GISRRJ | Volume 6 | Issue 1 | ISSN : 2582-0095

21वीं सदी के भारत में शिक्षा की उभरती चुनौतियाँ और शिक्षा बजट –एक समीक्षात्मक अध्ययन

डॉ उषा ओझा

सहायक प्राध्यापिका, तथागत टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज,धनबाद, झारखण्ड

Article Info

Publication Issue :
Volume 6, Issue 1
January-February-2023
Page Number : 43-50

Article History
Accepted : 01 Feb 2023
Published : 25 Feb 2023

शोध सार : अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा लायी गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति– 2020 ने देश में शिक्षा पर एक नई बहस को जन्म दिया है । बहस अपरिहार्य है क्योंकि यह शिक्षा नीति तय करेगी की 21 वीं सदी के भारत की शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी । बदलते सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी एवं पर्यावरणीय परिस्थिति में समकालीन समाज के अनुरूप प्रत्येक स्तर पर शिक्षा व्यवस्था को पुनर्संरचित एवं पुनर्व्यवस्थित कर मजबूत बनाना जरुरी होता है । निश्चित रूप से यह शिक्षा नीति भारतीय समाज की उभरती चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में भारतीय शिक्षा को नई दिशा देने वाला अहम दस्तावेज है । किंतु जानकारों की माने तो सबसे बड़ी चिंता इसे सफलता पूर्वक लागु करने में है । ऐसा इसलिए है क्योंकि मौजूदा समय कई चुनौतियां हैं जो नई शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन के समक्ष बड़ी बाधा के रूप में खड़ीं हैं – शिक्षा बजट इसमें सबसे बड़ी चुनौती है । अत: वर्तमान आलेख 21वीं सदी के भारत में शिक्षा की उभरती चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा में सुधार हेतु बजटीय आवंटन की समीक्षा प्रस्तुत करता है । यह अध्ययन मुख्य रूप से द्वितीयक आंकड़ों के गहन विश्लेषण पर आधारित है एवं इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय शिक्षा की मौजूदा एवं उभरती चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में वित्तीय प्रावधानों की समीक्षा कर सुधार हेतु सुझाव प्रस्तुत करना है ।

कुंजी शब्द : 21वीं सदी, भारत, शिक्षा बजट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ।

परिचय : हम जानते हैं कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है और इसमें भी सबसे बड़ी आबादी विद्यार्थियों की है । अर्थात भारत में मानव संसाधन के विकास की आपार संभावनाएं हैं । विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था वाला यह देश उपलब्ध विपुल प्राकृतिक संसाधनों का अपेक्षित उपयोग की संभावनाओं से विकासकेंद्रित निवेश के लिए विश्व को आकर्षित कर रहा है । एक ओर जहाँ भारत 21वीं सदी के मुख्य सूत्रधारकों में एक है, ग्लोबल लीडर के रूप में यहाँ के एक–एक लोगों को गुणात्मक एवं मात्रात्मक रूप से शिक्षित करना अपरिहार्य हो जाता है । दूसरी तरफ भारत हमेशा से चिंतनशील एवं सृजनशील मानव मस्तिष्क की जन्म भूमि रही है जिसे पश्चिम ने भी स्वीकारा है इसलिए भरतीय संस्कृति के परम्परागत मूल्यों की पुनर्स्थापना जरुरी है जिसे शिक्षा के माध्यम से ही पूरा किया जा सकता है । बड़े पैमाने पर शैक्षिक अवसंरचना के साथ – साथ बुनयादी अवसंरचना का विकास, इन–सर्विस फैकल्टी ट्रेंनिंग की देशव्यापी व्यवस्था, केंद्र एवं राज्य स्तर पर विवादों का निपटारा, समुदाय स्तर पर भागीदारी, लालफितासाही पर नियंत्रण, शिक्षा के राजनीतिकरण, प्रभावशाली योजनाओं का निर्माण , कानूनों एवं संवैधानिक प्रावधानों को सबकी सहमती से लाना, अधिक से अधिक फण्ड की आवश्यकता को पूरा करना ,

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Shauryam Research Institute. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

पहले से व्याप्त सामाजिक – आर्थिक विषमता की समस्या आदि कई ऐसे बुनयादी मसलें हैं जो 21 वीं सदी के भारतीय शिक्षा के समक्ष गंभीर चुनौतियाँ है । इस परिप्रेक्ष्य में शिक्षा का बजट कितना हो और इसे कैसे पूरा किया जाएगा यह एक चिंतनीय प्रश्न है ।

21वीं सदी के भारत में शिक्षा की उभरती चुनौतियाँ

भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला एक विशाल देश है। शिक्षा मंत्रालय से उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2019–20 के लिए भारत में स्कूलों और उच्च शिक्षा में कुल नामांकन 27.37 करोड़ था। 2021 तक भारत की कुल जनसंख्या लगभग 1.39 बिलियन या 139 करोड़ होने का अनुमान है **(विश्व बैंक, 2021)**। इसलिए, भारत की लगभग 19.69% आबादी 2019–20 तक स्कूलों और उच्च शिक्षा में नामांकित है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, भारत में साक्षरता दर 74.04% है **(भारत की जनगणना, 2011)**। 2018–19 तक, भारत में प्राथमिक शिक्षा के लिए सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 99.2% था, जबकि उच्च प्राथमिक शिक्षा के लिए यह 92.8% था। माध्यमिक शिक्षा के लिए जीईआर 60.7% था, जबकि उच्च शिक्षा के लिए यह 26.3% था **(शिक्षा मंत्रालय, 2020)**। 2018–19 तक, भारत में कुल 15,07,869 स्कूल थे। इनमें से 10,53,523 प्राथमिक विद्यालय थे, 3,13,708 उच्च प्राथमिक विद्यालय थे, 1,10,998 माध्यमिक विद्यालय थे, और 29,640 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय थे **(शिक्षा मंत्रालय, 2020)**। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआईएसएचई) के अनुसार, भारत में केवल 993 विश्वविद्यालय और 39,931 कॉलेज हैं **(एआईएसएचई, 2020)**। शिक्षा रिपोर्ट की वार्षिक स्थिति 2018–19 तक, प्राथमिक शिक्षा के लिए महिला जीईआर 94.3% थी, जबकि उच्च प्राथमिक शिक्षा के लिए यह 86.5% थी **(शिक्षा मंत्रालय, 2020)**।(एएसईआर) 2018 के अनुसार, 6–17 वर्ष के आयु वर्ग के छात्रों के लिए ड्रॉपआउट दर 4.9% थी **(एएसईआर केंद्र, 2018)।** भारत में शिक्षा के संदर्भ में उपरोक्त तथ्य इस बात को इंगित करता है कि शिक्षा के मामले में भारत ने विगत वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति की है किंतु अभी भी कई चुनौतियां है जिसका समाधान जरुरी है जैसे –

- **स्कूल के बुनियादी ढांचे की आवश्यकता:** स्कूल जाने वाले बच्चों की बढ़ती संख्या के साथ, भारत ने शिक्षा तक पहुंच में सुधार करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। हालांकि, पर्याप्त बुनियादी ढांचे की कमी के कारण शिक्षा की गुणवत्ता एक बड़ी चिंता बनी हुई है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) की एक रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण भारत के केवल 8.6% स्कूलों में बिजली, पीने का पानी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं (NSSO, 2018)। इसी तरह, कक्षाओं और योग्य शिक्षकों की कमी देश के कई हिस्सों में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में एक बड़ी चुनौती है। स्कूलों में बुनियादी ढाँचे के विकास की आवश्यकता को कोविड–19 महामारी द्वारा और अधिक उजागर किया गया है, जिसने स्कूलों के लिए ऑनलाइन सीखने के लिए डिजिटल तकनीक और इंटरनेट कनेक्टिविटी तक पहुँच बनाना आवश्यक बना दिया है। हालांकि, भारत में कई स्कूलों में ऐसी तकनीक तक पहुंच नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप छात्रों के लिए शिक्षा में काफी व्यवधान आया है।

- **उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे की आवश्यकता:** भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली को बुनियादी ढांचे की कमी और अनुसंधान और विकास के लिए धन की कमी सहित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआईएसएचई) के अनुसार, भारत में केवल 993 विश्वविद्यालय और 39,931 कॉलेज हैं (एआईएसएचई, 2020)। यह 1.3 अरब से अधिक आबादी वाले देश के लिए अपर्याप्त है, जहां उच्च शिक्षा की महत्वपूर्ण मांग है। इसके अलावा, भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बुनियादी ढांचे की कमी से प्रभावित होती है, जिसमें अपर्याप्त कक्षाएं, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं और अन्य सुविधाएं शामिल हैं। यह भारत में अनुसंधान और नवाचार के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा है, क्योंकि ये सुविधाएं एक ऐसा वातावरण बनाने के लिए आवश्यक हैं जो रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा दे।
- **डिजिटल डिवाइड:** राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) की एक रिपोर्ट के अनुसार, शहरी परिवारों के 42% की तुलना में केवल 23% ग्रामीण परिवारों के पास इंटरनेट की सुविधा है। महामारी के दौरान यह डिजिटल विभाजन ऑनलाइन शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा रहा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों और कम आय वाले परिवारों के छात्रों के पास डिजिटल बुनियादी ढांचे तक पहुंच नहीं है।

- **शिक्षा की गुणवत्ता:** विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में पाया गया कि भारत में शिक्षा की गुणवत्ता एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में छात्रों का एक बड़ा हिस्सा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल हासिल नहीं कर रहा है। इसके अलावा, शिक्षण की गुणवत्ता देश भर में एक समान नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच रखने वाले और नहीं करने वाले छात्रों के बीच विभाजन बढ़ता जा रहा है।
- **शिक्षा का निजीकरण:** ऑक्सफैम इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, शिक्षा के निजीकरण के परिणामस्वरूप संपन्न परिवारों के छात्रों के बीच विभाजन बढ़ गया है जो निजी शिक्षा का खर्च उठा सकते हैं और कम आय वाले परिवारों के छात्र जो नहीं कर सकते हैं। रिपोर्ट में पाया गया कि निजी स्कूल अक्सर अत्यधिक फीस वसूलते हैं, जो कई परिवारों के लिए वहन करने योग्य नहीं है। इसके परिणामस्वरूप निजी और सरकारी स्कूलों में छात्रों के बीच शिक्षा के परिणामों में महत्वपूर्ण अंतर आया है।
- **शिक्षा बजट:** शिक्षा के अधिकार के लिए राष्ट्रीय अभियान की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में शिक्षा के लिए धन का आवंटन अपर्याप्त रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि शिक्षा पर सरकार का खर्च वर्षों से घट रहा है, और शिक्षा क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए धन का आवंटन अपर्याप्त है। इसके परिणामस्वरूप बुनियादी ढांचे, शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान में निवेश की कमी हुई है।

- **अपर्याप्त शिक्षक प्रशिक्षण:** नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम अपर्याप्त हैं और शिक्षकों को प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल से लैस नहीं करते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि व्यावहारिक कौशल और कक्षा प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को फिर से डिजाइन करने की आवश्यकता है।

- **समावेशी शिक्षा की आवश्यकता:** भारत में, बच्चों के एक महत्वपूर्ण अनुपात के पास शिक्षा तक पहुंच नहीं है। शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (एएसईआर) 2020 के अनुसार, 6-17 वर्ष के आयु वर्ग के केवल 59% बच्चों के पास ऑनलाइन सीखने के लिए स्मार्टफोन या कंप्यूटर तक पहुंच है (एएसईआर, 2021)। इसके अलावा, दलितों, आदिवासियों और मुसलमानों जैसे वंचित समुदायों के बच्चों को गरीबी, भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार के कारण शिक्षा प्राप्त करने में महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ता है। विकलांग बच्चों को भी भारत में शिक्षा प्राप्त करने में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) की एक रिपोर्ट के अनुसार, केवल 2.2% विकलांग बच्चे स्कूलों में नामांकित हैं (NSO, 2018)। स्कूलों और कॉलेजों में पहुंच और समावेशी प्रथाओं की कमी विकलांग बच्चों के लिए सीखने में एक महत्वपूर्ण बाधा है। समावेशी शिक्षा इन चुनौतियों से निपटने और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि सभी बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच हो। समावेशी शिक्षा अभ्यास एक अधिक न्यायसंगत और समावेशी शिक्षा प्रणाली बनाने में मदद कर सकता है जो सभी छात्रों की विविध आवश्यकताओं को संबोधित करता है।

भारत में शिक्षा बजट –एक समीक्षा : शिक्षा किसी भी देश के विकास और प्रगति के लिए एक आवश्यक तत्व है। भारत में, शिक्षा प्रणाली अपर्याप्त बुनियादी ढांचे, शिक्षा की खराब गुणवत्ता और अपर्याप्त धन सहित कई चुनौतियों का सामना कर रही है। शिक्षा के लिए सरकार का बजटीय आवंटन कम रहा है, और शिक्षा क्षेत्र को बजट में कटौती का सामना करना पड़ रहा है। भारत सरकार ने लगातार शिक्षा के लिए बजटीय आवंटन बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई है। हालांकि, शिक्षा के लिए वास्तविक बजटीय आवंटन जीडीपी की तुलना में कम रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, सरकार का लक्ष्य शिक्षा बजट को जीडीपी के 6% तक बढ़ाने का है। हालाँकि, 2021-22 के बजट में, शिक्षा के लिए आवंटन जीडीपी का केवल 3.4% था (वित्त मंत्रालय, 2021)। यह राशि शिक्षा क्षेत्र के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए अपर्याप्त है।

तालिका संख्या -01

पिछले दस वित्तीय वर्ष में शिक्षा के लिए आवंटन

वित्तीय वर्ष	शिक्षा के लिए आवंटन (करोड़ रूपये में)	कुल बजट का प्रतिशत	कुल जी.डी.पी.का प्रतिशत
2014–15	67,398	3.74%	2.9%
2015–16	69,074	3.84%	2.7%
2016–17	72,394	3.72%	2.5%
2017–18	79,685.95	3.71%	2.7%
2018–19	85,010.32	3.48%	2.7%
2019–20	94,853.64	3.16%	3.1%
2020–21	99,311.52	4.62%	3%
2021–22	93,224.31	6.13%	3.1%
2022–23	1.04 लाख	8.0%	लगभग 3%
2023–24	1.12 लाख	8.3%	लगभग 3%

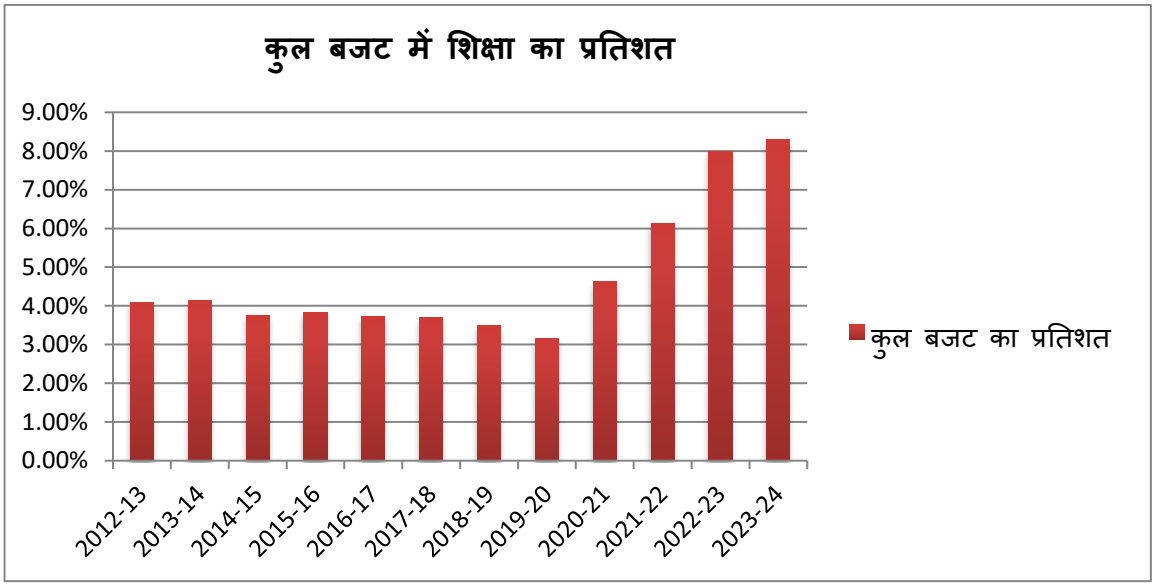

(स्त्रोत : केंद्रीय बजट, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार)

उपरोक्त आंकड़ों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि बजट की राशी में निरंतर वृद्धि तो हुई है और यह स्वाभाविक भी है किंतु जीडीपी में यह बढ़ोतरी 2.5 –3.0 प्रतिशत के बिच रहा है जो एक तरह से नगण्य है । अपर्याप्त बजटीय आवंटन के परिणामस्वरूप शिक्षा क्षेत्र में कई समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। प्रमुख समस्याओं में से एक पर्याप्त बुनियादी ढांचे की कमी है। ग्रामीण क्षेत्रों के कई स्कूलों में कक्षाओं, फर्नीचर और स्वच्छता सुविधाओं सहित उचित बुनियादी ढांचा नहीं है। बुनियादी ढांचे की कमी शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करती है, और छात्र उपयुक्त वातावरण में सीखने में असमर्थ होते हैं। दूसरी समस्या शिक्षकों की कमी है। कम बजटीय आवंटन के परिणामस्वरूप शिक्षकों को भर्ती करने के लिए धन की कमी हो गई है, और कई स्कूलों को अपर्याप्त कर्मचारियों के साथ प्रबंधन करना पड़ता है। यह शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करता है, और छात्रों को पर्याप्त मार्गदर्शन और सहायता प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं। अपर्याप्त बजटीय आवंटन के परिणामस्वरूप शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए संसाधनों की कमी भी हुई है। शिक्षा क्षेत्र को अनुसंधान और विकास, शिक्षकों के प्रशिक्षण और शैक्षिक प्रौद्योगिकी के विकास के लिए धन की आवश्यकता है। हालांकि, कम बजटीय आवंटन के कारण, इन क्षेत्रों को अक्सर उपेक्षित किया जाता है। अत: शिक्षा के लिए अपर्याप्त बजटीय आवंटन एक महत्वपूर्ण चुनौती है जिसका भारत का शिक्षा क्षेत्र सामना कर रहा है। सरकार को शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए शिक्षा बजट बढ़ाने और शिक्षा क्षेत्र के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता है। धन का आवंटन इस तरह से किया जाना चाहिए जो समान वितरण सुनिश्चित करे और समाज के वंचित वर्गों की जरूरतों को प्राथमिकता दे।

निष्कर्ष : 21वीं सदी के भारत के शैक्षिक बजट में कई प्रमुख क्षेत्रों में निवेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश की शिक्षा प्रणाली तेजी से बढ़ती आबादी और उभरती अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा कर सके। सबसे पहले, सरकार को प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए धन आवंटित करना चाहिए। इसमें योग्य शिक्षकों को काम पर रखना और प्रशिक्षण देना, आधुनिक शैक्षिक मानकों को दर्शाने के लिए पाठ्यक्रम को अद्यतन करना और स्कूलों में बुनियादी ढांचे में सुधार करना, जैसे स्वच्छ पानी और कार्यात्मक शौचालय प्रदान करना शामिल है । साथ ही सरकार को उच्च शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण तक पहुंच बढ़ाने को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसमें नए विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में निवेश करना, कम आय वाले छात्रों को छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता प्रदान करना और युवाओं को आज के रोजगार बाजार में सफल होने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार करना शामिल है। साथ ही सरकार को नवाचार को बढ़ावा देने और भारत की अर्थव्यवस्था के विकास का समर्थन करने के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (एसटीईएम) जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास में निवेश करना चाहिए। सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले वंचित समुदायों के लिए शिक्षा के परिणामों में सुधार करने की पहल को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसमें लड़कियों और महिलाओं के लिए शिक्षा की पहुंच बढ़ाना, सरकारी स्कूलों में प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना और शिक्षा में प्रणालीगत असमानताओं को दूर करने के लिए कार्यक्रमों में निवेश करना शामिल है। इस प्रकार भारत के दीर्घकालिक आर्थिक विकास और सामाजिक विकास के लिए शिक्षा में निवेश महत्वपूर्ण है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास जैसे

प्रमुख क्षेत्रों में निवेश को प्राथमिकता देकर और वंचित समुदायों के लिए परिणामों में सुधार की पहल करके, भारत यह सुनिश्चित कर सकता है कि इसकी शिक्षा प्रणाली 21 वीं की चुनौतियों और अवसरों का सामना करने के लिए तैयार है।

संदर्भग्रंथ सूचि :

1. All India Survey on Higher Education. (2020). Ministry of Education, Government of India. Retrieved from https://aishe.nic.in/aishe/dashboard
2. Annual Status of Education Report. (2021). ASER 2020 Wave 1 Findings. Pratham Education Foundation. Retrieved from https://img.asercentre.org/docs/Publications/ASER%202020/Release%20Material/aser2020release.pdf
3. ASER Centre. (2018). ASER 2018 India National Report. Retrieved from https://img.asercentre.org/docs/Publications/ASER%20Reports/ASER%202018/National%20PPTs/aser2018indiaenglish.pdf
4. Census of India. (2011). Literacy Rate. Retrieved from https://www.censusindia.gov.in/2011census/C-16.html
5. Government of India. (2021). Budget Speech. Retrieved from https://www.indiabudget.gov.in/doc/BudgetSpeech.pdf
6. Khan, A. (2018). The challenges of education in India: Can technology help? UNESCO-UIS. Retrieved from http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/the-challenges-of-education-in-india-2018-en.pdf
7. Ministry of Education. (2020). Statistical Year Book 2020. Retrieved from https://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/StatisticalYearBook2020.pdf
8. Ministry of Finance. (2021). Budget Speech. Retrieved from https://www.indiabudget.gov.in/doc/BudgetSpeech.pdf
9. National Education Policy 2020. (2020). Ministry of Education, Government of India. Retrieved from https://www.mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf
10. National Sample Survey Office. (2018). Key Indicators of Social Consumption in India: Education. Ministry of Statistics and Programme Implementation,

Government of Ind ia. Retr ieved from http://www.mosp i.gov. in/s ites/defau lt/f i les/pub i icat ionreports/K i

11. Nat iona i Stat ist ica i Off ice. (2018). D isab led Persons in Ind ia: A Stat ist ica i Prof i ie. M in istry of Stat ist ics and Programme Imp lementat ion, Government of Ind ia. Retr ieved from http://mosp i.n ic. in/s ites/defau lt/f i les/pub i icat ionreports/D isab iedpersons in Ind ia 2018.pdf
12. Pate i, D. (2019). Cha i lenges in Ind ian educat ion system: A rev iew. Internat iona i Journa i of Sc ient if ic and Research Pub i icat ions, 9(2), 171-173.
13. Reddy, M. (2019). Emerg ing cha i lenges in h igher educat ion in Ind ia. Internat iona i Journa i of Advanced Research in Educat ion & Techno logy (IJARET), 6(2), 111-116.
14. S ingh, A. K., & S ingh, R. (2019). Emerg ing cha i lenges of educat ion in Ind ia: A rev iew. Journa i of Educat ion and Pract ice, 10(32), 72-80.
15. Venkatesh, S., & Sambandam, C. (2020). Emerg ing cha i lenges in Ind ian h igher educat ion. Journa i of Advanced Research in Dynam ica i and Contro i Systems, 12(Spec ia i Issue 3), 1313-1319.
16. Wor id Bank. (2018). Address ing educat ion qua i ity in Ind ia. Wash ington, DC: Wor id Bank. Retr ieved from https://openknow ledge.wor idbank.org/b itstream/hand le/10986/30512/Address ing-Educat ion-Qua i ity- in- Ind ia.pdf?sequence=3& isA i lowed=y